IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण :मध्य प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में

आनंद तिवारी
शोध छात्र, राजनीती विज्ञान एवं लोक प्रशासक विभाग
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, (म.प्र.)

सारांश: मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 73 वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सम्पूर्ण भारत वर्ष में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है । जबकि मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में यह आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है । यह प्रावधान कही-न-कही लैंगिक समानता की ओर प्रदर्शित किया है जिससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला है, उत्पादकता और विकास में तेजी आयी है । प्रस्तुत लेख में मध्य प्रदेश के पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका एवं पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वितीयक आंकड़ों का संकलन कर, विश्लेषण एवं निर्वचन किया है । इससे यह ज्ञात हुआ है कि ग्राम पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है परन्तु इसके बावजूद भी प्रदेश में लैंगिक असमानताएं देखने को मिलती है । ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अच्छे काम तक पहुंच की कमी है और उन्हें व्यावसायिक अलगाव और लैंगिक वेतन अंतर का सामना करना पड़ता है । उन्हें अक्सर बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच से वंचित कर दिया जाता है । यहाँ तक कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को हिंसा और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है । आर्थिक और राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम है ।

शब्द कुंजी- मध्य प्रदेश; पंचायती राज; महिला सशक्तिकरण

सन्दर्भ-सूची

[1]. अली, परवेज और पाण्डेय, आशुतोष (2021), पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका: झारखण्ड के विशेष सन्दर्भ में, अपनी माटी.

[2]. झा, प्रीती (2021), पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण, सरपंच और सभी 13 पंच महिलाएं, https://www.jagran.com/madhya-pradesh/bhopal-50-percent-reservation-for-women-in-panchayati-raj-institutions-sarpanch-and-all-13-panch-women-22784146.html 08 जून 2022, 1:53PM

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 2, Issue 1, November 2022
Impact Factor: 6.252

[3]. सिंह, सीमा एंड अंतरा (2020), वोमेन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया: ए क्रिटिकल एनालिसिस, ताप्ति युजीसी जर्नल, 19(44),पृष्ठ-227-253.

[4]. पंचायत निर्वचन 2020, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 2019

[5]. कुमार, संतोष (2019), पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ पोलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस, 2(2), पृष्ठ-25-29.

[6]. पूनम (2019), एस्टडी ऑन पोलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ़ वोमेन इन लोकल गवर्नेंसइन हरयाणा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिविएव, 6(1)पृष्ठ-293-300.

[7]. सिंगला, पामेला, विमेंस पार्टिसिपेशन इन पंचायतीराज : नेचर एंड इफेक्टिवनेस (एनार्थ इंडियनपर्स पेक्टिव), रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2016.

[8]. ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच एवं पंचप्रशिक्षण मार्गदर्शिका 2015 म. प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश.

[9]. मीना, सोनू (2014), पंचायतीराज में महिला नेतृत्व : सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन, कोटा विश्वविद्यालय, सामाजिक विज्ञान संकाय, पृष्ठ-1-272.

[10].कुमार, रमेश (2013), डीसेंट्रलाजेसन एंड पोलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ़ वोमेन इन इंडिया, इंडियन जर्नल ऑफ़ फ़ेडरल स्टडीज, वॉल्यूम 14.

[11].अम्बेडकर एंड नागेन्द्र शैलजा, रोल ऑफ़ वोमेन: इन पंचायतीराज, एबीडी पब्लिकेशन, जयपुर, 2006

[12].https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1658145

[13].मध्यप्रदेश के जिलेवार समाजार्थिक विकास संकेतांक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश, 2014-15*2015-16.